VI दैनिक जागरण नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2022

संजय वन के संरक्षण को डीडीए व डब्ल्यूडब्ल्यूएफ में हुआ करार

- लर्निंग विद नेचर अभियान के तहत एक साथ काम करेंगी दोनों संस्था
- करार का उद्देश्य लोगों को प्रकृति के साथ सीखने का अवसर देना

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : डीडीए और वर्ल्ड वाइड फंड फार नेचर-इंडिया (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया) मिलकर दक्षिणी दिल्ली स्थित संजय वन में प्राकृतिक वनस्पति और जीव-जंतुओं के संरक्षण से लेकर उनकी गतिविधियों पर निगरानी और वन के प्राकृतिक व ऐतिहासिक धरोहरों को भी संरक्षित रखेंगे। लर्निंग विद् नेचर अभियान के तहत काम किया जाएगा। इसी अभियान को लेकर दोनों संस्थाओं के बीच करार हुआ।

डीडीए अधिकारी ने बताया कि संजय वन में प्रकृति आधारित शिक्षा और नेचर से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया के साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों संस्थान मिलकर लगभग 783 एकड़ में फैले संजय वन में पारिस्थितिक जैव विविधता संरक्षण और प्रकृति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ज्ञान और गतिविधि भागीदार के रूप में कार्य करेंगे। विभिन्न लोगों विशेष रूप से बच्चों में प्रकृति के साथ समझ और लगाव पैदा करने के उद्देश्य से यह अभियान सहायक साबित होगा। शहर की प्राकृतिक विरासत को लेकर भी जागरुकता और 'शैक्षिक अनुसंधान और वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण भी किया जाएगा।

डीडीए अधिकारी ने बताया कि संजय वन दक्षिण-मध्य रिज का एक अभिन्न भाग है और एक अधिसूचित आरक्षित वन है। इस वन में 12वीं शताब्दी के ऐतिहासिक खंडहरों वाली प्राचीन अरावली श्रृंखला का भी एक भाग है। इसके साथ ही विविध प्रकार की वनस्पति और जीवों से संपन्न यह घना जंगल कई प्रकार के पक्षियों, सरीसृपों, तितलियों, स्तनधारियों आदि का घर है। उन्होंने कहा कि करार का उद्देश्य है कि लोगों को भी प्रकृति के साथ सीखने का अवसर मिल सके।

संजय वन में प्रकृति की ओर एक कदम

■ विस, नई दिल्ली : संजय वन में अपनी तरह का लर्निंग विद नेचर का अनुभव करवाने के लिए डीडीए और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ (वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर) इंडिया मिलकर काम करेंगे। डीडीए ने संजय वन में प्रकृति से सीखने और इस तरह के गतिविधियों के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया के साथ एमओयू साइन किया है।

783 एकड़ में फैला संजय वन, दक्षिण-मध्य रिज का हिस्सा है और रिजर्व फॉरेस्ट है। डीडीए ने बताया कि यहां पर होने वाली एक्टिविटी ट्री टैगिंग, नेचर वॉक, वनस्पतियों और जीवों को देखने का मौका, बच्चों के लिए एजुकेशनल ट्रिप आदि शामिल होंगे।

Hindustan Times

Delhi govt panel to streamline city's monsoon preparedness

NEW DELHI: The Delhi government has formed a committee to ensure better coordination among various agencies to deal with waterlogging and drain desilting during monsoon, an official order issued on Friday said.

The move came after Delhi deputy chief minister Manish Sisodia released the city government's Flood Order 2022 on Thursday.

The committee comprises officials from several government agencies including the New Delhi Municipal Council (NDMC), Municipal Corporation of Delhi (MCD), Irrigation and Flood Control (I&FC) department, Delhi Cantonment Board (DCB), Delhi Development Authority (DDA), Delhi Jal Board (DJB), Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation (DSIIDC), Delhi International Airport Limited (DIAL), National Highways Authority of India (NHAI), Indian Railways, Delhi Metro Rail Corporation (DMRC), and Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) among others, according to order.

On Thursday, Delhi saw waterlogging and snarls on key stretches after the city received its first monsoon rain, keeping the traffic personnel and officials of the civic agencies busy all day. HTC

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI • SATURDAY, JULY 2, 2022

Nature-based learning soon at Sanjay Van

New Delhi: Sanjay Van will offer nature-based learning and experiential activities. The Delhi Development Authority (DDA) has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with World Wide Fund for Nature, India (WWF India) for the notified reserved forest spread over an area of 783 acres approximately.

Sanjay Van is part of the ancient Aravalli Range with historic ruins of the 12th Century, DDA said in a statement, adding that the dense forest near Vasant Kunj with a rich diversity of flora and fauna is home to a number of birds, reptiles, butterflies, mammals, odonates, etc.

The MoU aims to establish activities based on "learning with nature" and facilitate experiential activities like tree tagging, nature walks, flora and fauna observation, children's educational activities, etc, along with educative signages, flora and fauna atlas and publications, and citizen science initiatives, it said.

DDA said that WWF India will act as the "knowledge and activity partner" and undertake educational research and conservation of flora and fauna. TNN

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- DATED----------

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2022

इलाके में डाली जा रही पानी की नई पाइप लाइनें : विशेष रवि

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली में कई इलाकों में पानी की किल्लत चल रही है। कई जगहों पर पाइप लाइन पुरानी होने के कारण मुश्किलें अधिक बढ़ गई हैं, जिससे इलाकों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है।

विशेष रवि

- पाइप लाइन पुरानी होने के कारण लीकेज से बर्बाद होता है पानी
- शिव नगर गली और कृष्णा नगर में डाली जा रही पानी की पाइप लाइन

करोल बाग से विधायक विशेष रवि ने बताया कि इलाके में पानी की नई पाइप लाइन डाली जा रही है। मोतिया खान डीडीए फ्लैट्स के एलआइजी, एमआइजी में टैंक है, लेकिन इसके पीछे के इलाके में पानी नहीं पहुंच पाता था, जिसे देखते हुए नई लाइन डाली जा रही है। उन्होंने बताया कि इसी तरह शिव नगर गली नंबर दो और कृष्णा नगर गली नंबर छह में भी पानी की पाइप लाइन डालने का कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि इलाके में किसी को पानी के लिए परेशान न होना पड़े, इसके लिए कार्य किए जा रहे हैं।

सुबह नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । 3 जुलाई 2022

जल्द शुरू होगा नरेला में बनने वाली जेल के निर्माण का काम

चार हजार से अधिक कैदियों को बंद करने की होगी क्षमता

Maneesh.Aggarwal @timesgroup.com

होंगे कड़े इंतजाम...

- गैंगस्टरों के मोबाइल फोन का इस्तेमाल रोकने के लिए किए जाएंगे विशेष प्रबंध
- नरेला जेल के चप्पे-चप्पे पर बेस्ट क्वॉलिटी के सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे
- यह भी कोशिश की जा सकती है कि नई जेल को एयर कूल बनाया जाए

नई दिल्ली : नरेला में बनने वाली तिहाड़ की नई जिला जेल में चार हजार से अधिक कैदियों को रखा जा सकेगा। तिहाड़ जेल के बाद यह दूसरी ऐसी जेल होगी। जहां सबसे अधिक कैदी बंद किए जा सकेंगे। अभी दूसरे नंबर पर यमुनापार की मंडोली जेल है। जहां 3,776 कैदियों को रखने की क्षमता है।

सूत्रों का कहना है कि नरेला जेल पूरी तरह से मोबाइल फोन जैमर से लैस होगी। जिससे कैदी चाहकर भी मोबाइल का इस्तेमाल ना कर सकें। यहां समय के हिसाब से 4जी या 5जी जैमर लगाए जाएंगे। कोशिश की जाएगी कि कैदी जेल के अंदर से मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना कर पाएं। इसके अलावा इस जेल की चार दीवारी भी इस तरह की बनाई जाएंगी। ताकि बाहर से जेल के अंदर कोई ड्रग्स और मोबाइल फोन ना फेंक सके। जिस तरह से अभी तिहाड़, रोहिणी और मंडोली जेलों में बाहर से यह प्रतिबंधित चीजें जेलों के अंदर थ्रो करके भेजने की कोशिशें की जाती हैं।

जेल में खतरनाक कैदियों और गैंगस्टरों को रखने के लिए भी ऐसी व्यवस्था की जाएगी। जिससे की इस तरह के कैदी जेल के अंदर से ही क्राइम की दुनिया में अपना वर्चस्व ना रख सकें। नरेला जेल के चप्पे-चप्पे पर बेस्ट क्वॉलिटी के सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ताकि कैदियों, कैदियों से मुलाकात करने आने वाले और जेल स्टाफ की तमाम गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके। यह भी कोशिश की जा सकती है कि नई जेल को एयर कूल बनाया जाए। जिससे कि भयानक गर्मी में कैदी लू से बच सकें। इसके मल्टी स्टोरी बनाए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। नरेला जेल के लिए डीडीए से अलॉट हुई 1.6 लाख स्कवायर मीटर जमीन में तिहाड़ और मंडोली जेल की तरह एक से अधिक जेल बनाई जाएंगी। नरेला जेल कैंपस में तीन से चार जेल बनाई जाएंगी। जबकि तिहाड़ में नौ और मंडोली में छह जेल हैं।

अधिकारियों का कहना है कि भले ही नरेला जेल कैंपस में तीन से चार जेल बनाए जाने का विचार है। लेकिन यहां कैदियों को रखने की क्षमता तिहाड़ जेल के बाद सबसे अधिक होगी। नरेला जेल में चार हजार से अधिक कैदियों को रखने की क्षमता होगी। नरेला जेल के एक बड़े हिस्से में जेल इंडस्ट्री भी लगाई जाएगी। कोशिश की जा रही है कि यहां कैदियों से काम कराने के लिए जो जेल इंडस्ट्री लगाई जाएगी। वह कई मायनों में तिहाड़ जेल से भी आधुनिक होगी। यहां कैदियों को कई तरह के वोकेशनल कोर्स कराने के लिए भी ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

DATED

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2022 दैनिक जागरण | 3

उपराज्यपाल **विनय कुमार सक्सेना** ने डीडीए, एमसीडी और अन्य विभागों को दिए निर्देश

मानसून में रोपें चंदन के 10,000 पौधे

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली में इस मानसून चंदन के दस हजार पौधे रोपे जाएंगे। उपराज्यपाल (एलजी) विनय कुमार सक्सेना ने रविवार को सुंदर नर्सरी के दौरे के दौरान सभी भूस्वामित्व वाले विभागों को निर्देश दिया कि वे अपने उद्यान, पार्कों और खाली जमीन पर चंदन के पौधे लगाएं।

वीके सक्सेना

एलजी ने कहा कि चंदन के पेड़ से विभाग आमदनी भी कर सकते हैं। एलजी ने डीडीए, एमसीडी, दिल्ली पार्क्स एंड गार्डन सोसाइटी, दिल्ली बायोडायवर्सिटी सोसाइटी और अन्य विभागों को भी सलाह दी है कि मानसून में ही चंदन का पौधा लगा लें। उन्होंने कहा कि सभी मिलकर इस पर काम शुरू करें तो 10 हजार चंदन के पेड़ दिल्ली में होंगे। एलजी ने सभी भूस्वामियों से अपने यहां चार-चार चंदन के पौधे रोपने की अपील की है। एलजी ने कहा कि संसाधन की कमी वाले किसान चंदन के दो पेड़ों से ही अपने बच्चों की शिक्षा पूरी कर सकते हैं। बाकी दो से उनके भविष्य के लिए सोच सकते हैं। उदाहरण देते हुए कहा कि एक चंदन का पेड़ 12 से 15 साल में तैयार होता है। मौजूदा दरों के अनुसार, 12-15 लाख रुपये में बिकता है। इस दर पर 10,000 चंदन के पेड़ तैयार होंगे तो उससे 12 से 15 हजार करोड़ मिलेंगे।

एलजी ने कहा कि चंदन के पौधे राजधानी की वनस्पति विविधता को जोड़ने और सामान्य वातावरण को समृद्ध करने के अलावा, सरकारी भूमि से आमदनी भी देंगे। शहर में भूमि देने वाली एजेंसियों और किसानों/भूमिधारकों के लिए वित्तीय मजबूती देगा। सुंदर नर्सरी के दौरे में उन्होंने खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में पिछले कार्यकाल में नासिक, वाराणसी, गांधी नगर व दिल्ली में सफलतापूर्वक चंदन के दो हजार पौधे लगाने के अनुभव के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के राजघाट में लगाया गया पौधा ना सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि अब करीब 10 फीट का हो गया है।

प्रदूषण मुक्त राजधानी के लिए एलजी ने जनता से मांगे सुझाव

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: सर्दी के मौसम में इस बार राजधानी गैस चैंबर न बने, इसके लिए दिल्ली और केंद्र सरकार तो कई अहम कदम उठा ही रही हैं। अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी प्रदूषण की समस्या को लेकर अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, दिल्ली के लोग सुझाव दें कि राष्ट्रीय राजधानी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए क्या किया जाए। साथ ही उन्होंने लोगों से इस समस्या को हल करने के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया है।

दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली की आबोहवा सर्दियों में ही खराब होती थी, लेकिन अब यह समस्या पूरे साल रहती है। इस मुद्दे पर केंद्र और दिल्ली सरकार में तकरार भी होती है। दिल्ली सरकार का दावा है कि यहां आधे से ज्यादा प्रदूषण पड़ोसी राज्यों की वजह से होता है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली का अपना प्रदूषण भी कम नहीं है।

उपराज्यपाल ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि दिल्ली वाले लगातार खराब व गंभीर वायु गुणवत्ता में सांस लेते हैं। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। अधिकांश प्रदूषण लोग खुद उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से साथ मिलकर दिल्ली को गैस चैंबर से मुक्त करने का संकल्प लेने का अनुरोध किया है। ताकि दिल्ली की हवा का सांस लेने योग्य बना सकें।

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
MONDAY, JULY 4, 2022

LG tells officials to plant 10,000 sandalwood trees

New Delhi: Lieutenant governor VK Saxena has directed all land owning agencies of the national capital to plant 10,000 sandalwood trees across the city to effectively monetise their land resource.

The LG has directed all government agencies that own huge tracts of land and maintain parks, gardens and undertake horticultural activities to plant 10,000 sandalwood trees across the city, the Raj Niwas said in a statement on Sunday.

It said that agencies like Delhi Development Authority (DDA), Municipal Corporation of Delhi (MCD), Delhi Parks and Garden Society, Delhi Biodiversity Society and others have been advised to complete plantation of these trees during the ongoing monsoon season.

On a visit to the Sunder Nursery Complex on Sunday, Saxena recounted his experience of getting 2,000 sandalwood trees planted last year at different locations like Nasik, Varanasi, Gandhi Nagar vicinity, as well as Delhi during his previous stint as the chairman of Khadi and Village Industries Commission (KVIC).

He said in the statement that contrary to the belief in certain circles that sandalwood trees cannot come up in climatic conditions present in Delhi and other locations in the country, all these trees — including the ones that he got planted at Rajghat in Delhi — had in an year not only survived, but grown to a robust height of 9-10 feet. TNN

हिन्दुस्तान
नई दिल्ली
सोमवार
4 जुलाई 2022

राजधानी में चंदन के दस हजार पेड़ लगेंगे : एलजी

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली में इस मानसून चंदन के पेड़ लगाने का काम भी शुरू होगा। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने रविवार को सुंदर नर्सरी के दौरे के दौरान दिल्ली के सभी भूस्वामित्व वाले विभागों को निर्देश दिया कि वे अपने उद्यान, पार्कों और खाली पड़ी जमीन पर चंदन के पेड़ लगाने का अभ्यास शुरू करें।

वायु प्रदूषण कम करने के लिए सुझाव मांगे

कूड़े का पहाड़ खत्म करने, यमुना को साफ करने का सुझाव मांगने के बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अब वायु प्रदूषण कम करने के लिए दिल्लीवालों से सुझाव है। रविवार को ट्विटर पर उन्होंने दिल्ली के वायु प्रदूषण का स्तर साझा करते हुए, उन्होंने दिल्लीवालों से अपने सुझाव देने के लिए कहा है। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के प्रदूषित हवा में सांस लेना दूभर है। दिल्ली का वायु प्रदूषण इंडेक्स बताता है कि दिल्ली की आबो हवा खराब है।

एलजी ने कहा कि चंदन के पेड़ लगाने से विभाग अपने भूमि संसाधनों से आमदनी भी कर सकते हैं। एलजी ने डीडीए, एमसीडी, दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसाइटी, दिल्ली बायो डायवर्सिटी सोसाइटी और अन्य विभागों को भी सलाह दी है कि मानसून में ही चंदन का पेड़ लगाएं। सभी मिलकर इसपर काम शुरू करें तो 10 हजार चंदन के पेड़ दिल्ली में होंगे।

बच्चों की शिक्षा पूरी हो सकेगी : उपराज्यपाल ने सभी भूस्वामियों से अपने यहां चार-चार चंदन के पेड़ लगाने की अपील की है। एलजी ने कहा कि संसाधन की कमी वाले किसान चंदन के दो पेड़ों से ही अपने बच्चों की शिक्षा पूरी कर सकते हैं। बाकी दो से उनके भविष्य के लिए सोच सकते हैं।

उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि एक चंदन का पेड़ 12 से 15 साल में तैयार होता है। मौजूदा दरों के अनुसार 12-15 लाख रुपये में बिकता है। इस दर पर 10,000 चंदन के पेड़ तैयार होंगे तो उससे 12 से 15 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। चंदन का वृक्षारोपण, राजधानी की वनस्पति विविधता को जोड़ने और सामान्य वातावरण को समृद्ध करने के अलावा, सरकारी भूमि से आमदनी को बढ़ावा भी देगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । सोमवार, 4 जुलाई 2022 ----DATED---- , MONDAY, JULY 4, 2022
THE INDIAN EXPRESS

दिल्ली में लगेंगे 10 हजार चंदन के पेड़

रविवार को उपराज्यपाल ने सुंदर नर्सरी परिसर का दौरा किया

■ **विस, नई दिल्ली :** दिल्ली में चंदन के 10 हजार पेड़ लगाए जाएंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डीडीए एमसीडी और बाकी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे इस मॉनसून सीजन में इसे लेकर पूरा काम कर ले। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के किसानों, जमीन मालिकों और फार्महाउस के मालिकों से भी अपील की है कि वे चार-चार चंदन के पेड़ लगाएं।

उपराज्यपाल ने चंदन के पेड़ लगाने के लिए उन सभी एजेंसियों को निर्देश दिया है, जो पार्क, बागान का रखरखाव करते हैं और जमीन के बड़े हिस्से के मालिक हैं। एलजी ने सभी से दिल्ली में 10 हजार पेड़ लगाने को कहा है ताकि भूमि संसाधनों से प्रभावी ढंग से आर्थिक फायदा लिया जा सके। डीडीए, एमसीडी, दिल्ली पार्क्स एंड गार्डन सोसाइटी, दिल्ली बायोडायवर्सिटी सोसाइटी और बाकी एजेंसियों को सलाह दी गई है कि मॉनसून के मौसम में ही इन पेड़ों को लगाने का काम पूरा कर लें।

उन्होंने शहर में फार्म हाउस मालिकों के अलावा किसानों से भी कम से कम चार चंदन के पेड़ लगाने की अपील की है। उनका कहना है कि संसाधन की कमी वाले किसान अपने बच्चों की शिक्षा के लिए दो पेड़ों पर निर्भर हो सकते हैं।

NBT नजरिया

दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी के लिए आम, पीपल, नीम और बरगद जैसे पेड़ ज्यादा उपयोगी साबित होंगे। चंदन के पेड़ को उगने के लिए खास तरह की जलवायु की तो उतनी जरूरत नहीं है लेकिन मिट्टी की गुणवत्ता बहुत महत्पूर्ण होती है। इसे बड़ा करना आसान नहीं क्योंकि चंदन को जमीन से जरूरी माइक्रो न्यूट्रेंट्स लेने के लिए एक होस्ट पौधे का साथ चाहिए होता है। अगर चंदन के पेड़ लगाने हैं तो इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा।

ईस्ट ऑफ कैलाशः खाली जमीन बन रही अब शराबियों का अड्डा

■ राम त्रिपाठी, ईस्ट ऑफ कैलाश

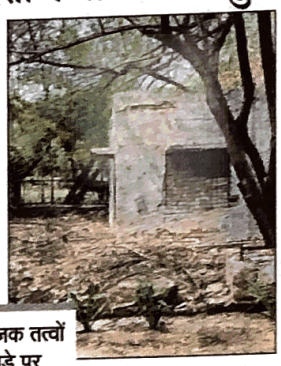

ईस्ट ऑफ कैलाश के 'डी' ब्लॉक में खाली पड़ी सरकारी जमीन अब शराबियों का अड्डा बन गई है। लोगों का कहना है कि एक सरकारी संपत्ति के वारिस का पता लगाने के लिए स्थानीय लोग पिछले 2 साल से डीडीए, एमसीडी, जल बोर्ड, फ्लड डिपार्टमेंट आदि को पत्र लिख चुके हैं। शिकायत के जवाब में सभी एजेंसियां उस संपत्ति पर दूसरी एजेंसी का अधिकार बता रही हैं। इसे लेकर अब लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर गुहार लगाई है। लोग यहां असामाजिक तत्वों के लगने वाले जमावड़े पर लगाम लगाने की मांग कर रहे हैं।

असामाजिक तत्वों के जमावड़े पर लगाम लगाने की मांग कर रहे लोग

स्थानीय निवासी करण अग्रवाल ने इस समस्या को लेकर पीएमओ को पत्र लिखा है। पत्र में बताया गया है कि 'डी' ब्लॉक में लगभग 2 सौ वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल की जमीन पर एक कमरा बना हुआ है। लोगों ने बताया कि वहां कभी ट्यूबवेल लगा था। कमरा अब जर्जर हालत में है। शाम होते ही यहां शराब पीने वालों का जमावड़ा लग जाता है। असामाजिक तत्वों का यह अड्डा बन चुका है। इससे इलाके की सुरक्षा को भी खतरा है। इसे लेकर लोग पुलिस से शिकायत भी कर चुके हैं। पुलिस की कार्रवाई के बाद कुछ दिन यहां शांति रहती है। कुछ दिन बाद फिर हालात जस के तस हो जाते हैं। एक सीनियर सिटीजन ने बताया कि ईस्ट ऑफ कैलाश में राजा धीर सिंह मार्ग के नजदीक ऐसी 2 और ट्यूबवेल की जगह हैं। अब वहां प्राइवेट टैक्सी वालों का कब्जा रहता है।

L-G tells MCD, DDA to plant 10k chandan trees

New Delhi: L-G Vinai Kumar Saxena Sunday directed the Delhi Development Authority, Municipal Corporation of Delhi and other agencies concerned to undertake a 'Sandalwood Plantation Drive' this monsoon and plant 10,000 trees across the city.

"The L-G has directed all landowning agencies that own huge tracts of land and maintain parks, gardens and undertake horticultural activities to plant 10,000 sandalwood (chandan) trees across the capital, so as to effectively monetise their land resources. Agencies like DDA, MCD, Delhi Parks & Garden Society, Delhi Biodiversity Society and others have been advised to complete the plantation of these trees during the ongoing monsoon season itself," said a statement shared by Raj Niwas.

Officials said a sandalwood tree matures in 12-15 years and as per the current rate, sells at Rs 12-15 lakh each. At this rate, 10,000 sandalwood trees are estimated to fetch between Rs 12,000-15,000 crore upon maturity. **ENS**

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NAME OF NEWSPAPERS NEW DELHI | SATURDAY, 2 JULY, 2022 TED----------

AT SANJAY VAN

DDA and WWF join hands for nature-based learning

SATVIKA MAHAJAN

NEW DELHI: The Delhi Development Authority (DDA) signed an MOU with the WWF India for "nature based learning and experiential activities" at Sanjay Van, New Delhi on Friday. The MoU aims to establish activities based on 'learning with nature' and facilitate experiential activities like tree tagging, nature walks, flora and fauna observation, children's educational activities etc., along with educative signages, flora and fauna atlas and publications, and citizen science initiatives.

Sanjay Van, spread over nearly 783 acres, is an integral part of the South-Central Ridge and is a notified "Reserved Forest", the DDA said. Located near Vasant Kunj, a part of ancient Aravalli Range with historic ruins of 12th century, the dense forest with a rich diversity of flora and fauna is home to a number of birds, reptiles, butterflies, odonates and mammals etc.

Its rich natural heritage is due to its distinct landscape with geomorphological features like rocky outcrops and water bodies, thus making it a haven for nature enthusiasts amidst the metropolis.

WWF India is committed to address conservation issues for securing ecological biodiversity and spreading educational awareness about nature and will act as the 'knowledge and activity partner' and also undertake 'educational research and conservation of flora & fauna' as part of the MoU. These activities at Sanjay Van will build a sense of appreciation for the city's natural heritage amongst the citizens of Delhi, especially children, to inculcate an understanding and bond with nature at an early and impressionable age.

DDA, besides regular maintenance and upkeep of the large green, has taken several initiatives like enhancement of the forest character through plantation, restoration and conservation of heritage structures with ASI, cleaning of the water bodies with DJB etc. The MoU with WWF India is another important initiative in this direction.

Delhi govt sets up panel on waterlogging

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: To ensure better coordination among various agencies in dealing with waterlogging issues and desilting of drains, the Delhi government has formed an inter-departmental committee headed by the PWD secretary, an official order said.

According to Delhi government's Flood Order 2022, which was released on Thursday by Deputy Chief Minister Manish Sisodia, the committee will monitor desilting of drains and sewers and address waterlogging problem at vulnerable points during the monsoon.

"For monitoring the activities of desilting of storm water drains and to address waterlogging issues, an inter-departmental coordination committee has been formed by consensus of all departments.

"Secretary, PWD is the coordination committee chairman. Meetings of the committee will be held on regular basis to resolve inter-departmental issues, monitor desilting works, monitor and check waterlogging vulnerable locations," the flood order said.

Officials from other government agencies including the NDMC, MCD, Irrigation and Flood Control (I&FC), Delhi Cantonment Board, Delhi Development Authority, Delhi Jal Board, Delhi State Industrial ad Infrastructure Development Corporation, Delhi International Airport Limited, National Highways Authority of India, Indian Railways, Delhi Metro Rail Corporation, Delhi Urban Shelter Improvement Board among others, will be the members of the coordination committee.

"The coordination committee will monitor activities including desilting of storm water drains and sewers, cleaning of municipal solid waste from drains, addressing and resolving waterlogging vulnerable locations to check recurrence, status of operation of storm water pumps, inspection and cross inspection of desilting works and operation of pumps and resolve inter-departmental issues," the order stated.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER पंजाब केसरी DATED 04/07/2022

आदेशः पार्कों और खाली पड़ी जमीन पर लगाए जाएंगे पेड़

दिल्ली में लगाए जाएंगे चंदन के दस हजार पेड़: उपराज्यपाल

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली को जल्द ही चंदन के पेड़ महकाएंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पार्क्स एंड गार्डन सोसाइटी, दिल्ली बायोडायवर्सिटी सोसाइटी और अन्य विभागों को मानसून में चंदन के पेड़ लगाने का आदेश दिया है।

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने रविवार को सुंदर नर्सरी के दौरे के दौरान दिल्ली के सभी भूस्वामित्व वाले विभागों को निर्देश दिया कि वे अपने उद्यान, पार्कों और खाली पड़ी जमीन पर चंदन के पेड़ लगाने का अभ्यास शुरू करें। चंदन के पेड़ लगाने से विभाग अपने भूमि संसाधनों से आमदनी भी कर सकते हैं। एलजी ने कहा कि सभी मिलकर इस पर काम शुरू करें तो 10 हजार चंदन के पेड़ दिल्ली में होंगे।

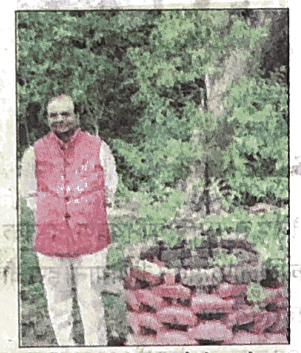

एलजी ने सभी भूस्वामियों से अपने यहां चार-चार चंदन के पेड़ लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि एक चंदन का पेड़ 12 से 15 साल में तैयार होता है। मौजूदा दरों के अनुसार 12-15 लाख रुपये में बिकता है। इस दर पर 10,000 चंदन के पेड़ तैयार होंगे तो उससे 12 से 15 हजार करोड़ रुपए मिलेंगे।

अनुभव साझा किया गया...

उपराज्यपाल ने कहा कि चंदन का वृक्षारोपण, राजधानी की वनस्पति विविधता को जोड़ने और सामान्य वातावरण को समृद्ध करने के अलावा, सरकारी भूमि से आमदनी को बढ़ावा भी देगा। शहर में भूमि देने वाली एजेंसियों और किसानों-भूमि-धारकों के लिए वित्तीय संपत्ति भी खड़ा करेगा। सुंदर नर्सरी के दौरे के दौरान उन्होंने केवीआईसी के अध्यक्ष के रूप में अपने पिछले कार्यकाल में नासिक, वाराणसी, गांधी नगर और दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर सफलतापूर्वक 2000 चंदन के पेड़ लगाने के अपने अनुभव के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के राजघाट में लगाया गया पेड़ ना सिर्फ बचा है, बल्कि अब नौ से दस फीट का हो गया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

4 जुलाई • 2022 | राष्ट्रीय सहारा

SPAPERS----------DATED----------

मानसून के दौरान 10 हजार चंदन के पौधे रोपें : एलजी

नई दिल्ली (एसएनबी)। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राजधानी में पाक और उद्यान का रखरखाव करने वाली और भू स्वामित्व रखने वाली एजेंसियों को इस मानसून सत्र के दौरान 10 हजार चंदन पौधे लगाने का निर्देश दिया है ताकि उनकी भू संपदा से आय हो सके।

उप राज्यपाल के सचिवालय राज निवास से रविवार को जारी बयान में कहा गया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली पार्क और उद्यान सोसाइटी, दिल्ली जैवविविधता सोसाइटी और अन्य को सलाह दी जाती है कि मौजूदा मानसून सत्र में चंदन के पौधे लगाने के कार्य को पूरा करें। यह निर्देश सक्सेना द्वारा रविवार को सुंदर नर्सरी का दौरा किए जाने के बाद आया।

सुंदर नर्सरी का दौरा करने के बाद उपराज्यपाल ने दिए निर्देश

सक्सेना ने कहा कि पादप विविधता को बढाने और आम तौर पर पर्यावरण को समृद्ध करने के साथ चंदन के पौधे लगाने से सरकारी जमीन से धन प्राप्ति भी हो सकेगी और दिल्ली में भू स्वामित्व रखने वाली एजेंसियों के लिए 'वृहद वित्तीय परिसंपत्ति'भी सृजित होगी। उप राज्यपाल ने कहा कि चंदन के पेड़ 12 से 15 साल में पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। मौजूदा दर पर प्रत्येक पेड़ को मौजूदा कीमत के हिसाब से 12 से 15 लाख रुपए में बेचा जा सकता है। इस कीमत पर 10 हजार चंदन के वृक्षों की अनुमानित कीमत 12 से 15 हजार करोड़ रुपये होगी। उन्होंने फार्म हाउस मालिकों के अलावा किसानों और छोटे आकार की जमीन का स्वामित्व रखने वालों से भी कम से कम चार चंदन के पौधे लगाने की अपील की।

अमर उजाला

चंदन की खुशबू से महकेगी दिल्ली की फिजा

नई दिल्ली। राजधानी की फिजा अब चंदन की खुशबू से महकेगी। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मानसून के दौरान ही 10,000 चंदन के पेड़ लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने रविवार को सुंदर नर्सरी का दौरा किया और नासिक, दिल्ली, वाराणसी और गांधी नगर में लगवाए गए 2,000 चंदन के पेड़ों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में राजघाट पर लगाए गए चंदन के पेड़ न केवल बच गए हैं, बल्कि इनकी ऊंचाई 9-10 फीट तक हो गई है।

इस मानसून राजधानी में 10,000 पेड़ लगाए जाएंगे

उपराज्यपाल ने डीडीए, एमसीडी, दिल्ली पार्क्स एंड गार्डन सोसाइटी, दिल्ली बायोडायवर्सिटी सोसाइटी और अन्य एजेंसियों को सलाह दी है कि मानसून के दौरान ही इन पेड़ों का रोपण पूरा कर लें ताकि उनके भूमि संसाधन को प्रभावी ढंग से मुद्रीकृत किया जा सके। ब्यूरो

दैनिक भास्कर

एलजी के निर्देश, मानसून में लगाएं 10 हजार चंदन के पौधे ताकि दिल्ली खुशबू से महके

फार्म हाउस मालिकों, किसानों और छोटे भूमि धारकों से 4 चंदन के पौधे लगाने की अपील की

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

अब जल्द दिल्ली चंदन की खुशबू से महकेगी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डीडीए और एमसीडी को दिए इस मानसून में नासिक, वाराणसी,गांधी नगर के तर्ज पर किसानों, संस्थाओं और फार्म हाउस मालिकों को 4 चंदन के पेड़ लगाने के लिए अपील करने का निर्देश दिया है। जिससे इस मानसून सीजन में 10 हजार चंदन का पेड़ लगाया जा सके। डीडीए, एमसीडी, दिल्ली पार्क्स एंड गार्डन सोसाइटी, दिल्ली बायोडायवर्सिटी सोसाइटी और अन्य एजेंसियों को सलाह दी गई है कि चल रहे मानसून के मौसम में ही चंदन के इन पेड़ों का रोपण पूरा कर लें।

उपराज्यपाल रविवार को सुंदर नर्सरी परिसर के दौरे पर बताया कि उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में केवीआईसी के अध्यक्ष के रूप में अपने पिछले कार्यकाल में नासिक, वाराणसी, गांधी नगर आसपास के साथ-साथ दिल्ली जैसे विभिन्न स्थानों पर सफलतापूर्वक 2,000 चंदन के पेड़ लगाए। उन्होंने बताया कि कुछ जगहों पर इस बात अफवाह है कि चंदन के पेड़ दिल्ली और देश के अन्य स्थानों में मौजूद जलवायु परिस्थितियों में नहीं आ सकते हैं। उपराज्यपाल ने बताया कि दिल्ली के राजघाट पर लगाए गए पेड़ भी शामिल हैं। एक साल में न केवल बच गया, लेकिन मजबूती से 9-10 फीट की ऊंचाई तक बढ़ गया है।

उपराज्यपाल ने फार्म हाउस मालिकों के अलावा किसानों और छोटे भूमि धारकों से भी कम से कम 4 चंदन के पेड़ लगाने की अपील की है। उपराज्यपाल ने कहा है कि ऐसा करने से सक्सेना ने रेखांकित किया, अक्सर संसाधन की कमी वाले किसान अपने बच्चों की शिक्षा के लिए आसानी से दो पेड़ों पर निर्भर हो सकते हैं और शेष दो का उपयोग उनके भविष्य के करियर में सहायता के लिए किया जा सकता है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NEW DELHI | MONDAY, 4 JULY, 2022

DIRECTIONS CAME AFTER THE L-G VISITED THE SUNDER NURSERY

Plant 10K sandalwood trees during monsoon season, says L-G Saxena

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Lieutenant Governor V K Saxena has directed all land owning agencies that maintain parks and gardens in Delhi to plant 10,000 sandalwood trees during the monsoon season to monetise their land resource, an official statement said on Sunday.

The statement issued by L-G's secretariat Raj Niwas said agencies like the Delhi Development Authority, MCD, Delhi Parks & Garden Society, Delhi Biodiversity Society and others have been advised to complete the plantation of sandalwood trees during the on-going monsoon season.

The directions came after Saxena visited the Sunder Nursery here on Sunday.

L-G V K Saxena

'A sandalwood tree matures in 12 to 15 years and as per the current rates, sells at Rs 12-15 lakh each'

Saxena said apart from adding to the flora diversity and enriching the general environs, the plantation of sandalwood will lead to monetisation of government land and create "immense financial assets" for the land owing agencies in Delhi.

"A sandalwood tree matures in 12 to 15 years and as per the current rates, sells at Rs 12- 15 lakh each. At this rate, 10,000 sandalwood trees are estimated to fetch between Rs 12,000 -15,000 crore upon maturity," the statement quoting the L-G said. He also appealed to farmers and small land holders apart from farm house owners in the city to plant at least four sandalwood trees.

He said sandalwood plantation will also create assets for self-sustainability, generate employment and support the Indian sandalwood, sandalwood oil and perfume industry that depends on importing large quantities of sandalwood oil and powder.

On his visit to the Sunder Nursery Complex on Sunday, the L-G recounted his experience of successfully getting 2,000 sandalwood trees planted last year at different locations in Nasik, Varanasi, Gandhi Nagar as well as Delhi in his previous stint as the Chairman, KVIC, the statement said.

"The L-G said contrary to refrain in certain circles that chandan trees cannot come up in climatic conditions present in Delhi and other locations in the country, all these trees, including the ones that he got planted at Rajghat in Delhi, had in an year not only survived, but robustly grown to a height of 9-10 feet," the statement said.

the pioneer

Plant 10K chandan trees: LG

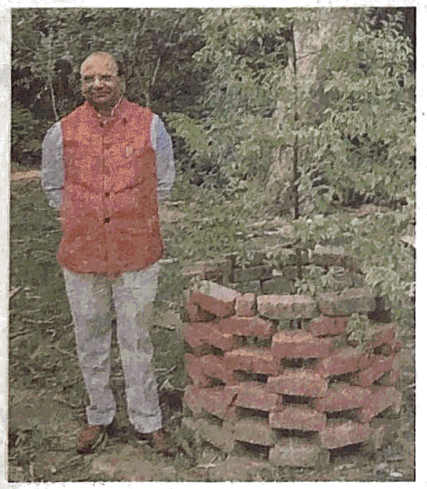

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The Lieutenant Governor (L-G), V K Saxena, has directed all land owning agencies to undertake horticultural activities to plant 10,000 sandalwood (chandan) trees across the national Capital, so as to effectively monetise their land resource. The L-G has also appealed to farmers and small land holders apart from farm house owners in the city to plant at least four chandan trees. According to officials, the agencies like DDA, MCD, Delhi Parks and Garden Society, Delhi Biodiversity Society and others have been advised to complete the plantation of these trees during the on-going monsoon season itself.

"By doing so, the often resource deficient farmers could easily depend on two trees for the education of their children and the remaining two could be utilized for aiding their future careers," said Saxena.

"Plantation of Sandalwood, apart from adding to the flora diversity of the city and enriching the general environs, will lead to monetization of government land and create immense financial assets for the land-owning agencies and farmers and land-holders in the city," said the official.

"A sandalwood tree matures in 12 to 15 years and as per the current rates, sells at Rs 12- 15 lakh each. At this rate, around 10,000 sandalwood trees are estimated to fetch between Rs 12,000 -15,000 crores upon maturity," said the official.

The L-G informed that contrary to refrain in certain circles that chandan trees cannot come up in climatic conditions present in Delhi and other locations in the country, all these trees, including the ones that he got planted at Rajghat in Delhi, had in an year not only survived, but robustly grown to a height of 9-10 feet.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE HINDU DELHI
MONDAY, JULY 4, 2022
NAME OF NEWSPAPERS----------DATED----------

HC halts demolition drive at Sarai Kale Khan slum cluster

Authorities say the slum dwellers are ineligible for rehabilitation

SOIBAM ROCKY SINGH
NEW DELHI

The Delhi High Court has ordered the Delhi Development Authority (DDA) to put on hold the demolition drive at Gyaspur Basti in Sarai Kale Khan here, which has 100 slums with over 460 residents, till further orders.

A Vacation Bench of Justice Neena Bansal Krishna noted that the documents submitted by the jhuggi (slum) dwellers showed that they are occupying the premises since 1995.

"Considering the long possession of the parties and their assertions that it is a jhuggi cluster having more than 100 jhuggis, the respondent (DDA) is directed to maintain status quo till July 11, 2022," Justice Krishna ordered.

'Illegal demolition'

The jhuggi dwellers contended that according to the Delhi Slum and JJ Rehabilitation and Relocation Policy 2015, the Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) is required to conduct a survey and plan a rehabilitation programme before carrying out the demolition. "None of the procedures have been followed," the jhuggi dwellers said, adding that the "arbitrary and illegal" demolition by the DDA would not only render them homeless but also jobless.

On June 27, the DDA had carried out an anti-encroachment drive on a stretch of the Yamuna floodplains in Sarai Kale Khan. Its officials said the exercise was carried out pursuant to the directions of the Supreme Court and guidelines of the National Green Tribunal.

Gyanpur Basti's residents told the High Court that the demolition was partial and several jhuggis are still intact.

Poor economic status

The petitioners submitted that the 'Basti' was established about forty years ago and they have residence proofs dating to 1995. Most of the residents migrated to Delhi from Uttar Pradesh and 95% of the residents belong to Scheduled Caste, "Dhobi caste" or other backward classes, the jhuggi dwellers said.

The plea added that the inhabitants are daily wagers living below the poverty line and are primarily engaged in unskilled or semi-skilled informal labour. Even as they are vulnerable to the COVID-19 pandemic, they are now worried about the possibility of illegal eviction and demolition of their houses.

The DDA vehemently argued that what has been termed as jhuggi clusters, are instead sporadic jhuggis that have come up in the area. "They do not qualify as a Basti or cluster and therefore, the Delhi Slum and JJ Rehabilitation and Relocation Policy 2015 is not applicable," the DDA said.

The DUSIB also submitted that the area in respect of which the petition has been filed does not qualify as clusters/basti and is not covered under the Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010. "The petitioners being encroachers are not entitled to any protection," the DUSIB said.

Justice Krishna relied on various judgments of the court to note that the agencies must first determine if the dwellers are eligible for rehabilitation in terms of the extant law and policy before forced eviction.

"Forced eviction of jhuggi dwellers, unannounced, in co-ordination with the other agencies and without compliance of the requisite procedures, would be contrary to law," Justice Krishna said.

The High Court further asked the DUSIB to consider providing temporary protection in a night shelter nearest to the jhuggi area to two applicants who have been rendered homeless as their jhuggis were demolished. The Bench posted the case for next hearing on July 11.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

the pioneer

NEW DELHI I SATURDAY I JULY 2, 2022

Delhi Govt sets up panel for coordination among agencies over waterlogging, desilting

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Delhi Government has formed an inter-departmental committee headed by the PWD secretary to ensure better coordination among various agencies in dealing with waterlogging issues and desilting of drains.

According to Delhi Government's Flood Order 2022, which was released on Thursday by Deputy Chief Minister Manish Sisodia, the committee will monitor desilting of drains and sewers and address waterlogging problem at vulnerable points during the monsoon.

"For monitoring the activities of desilting of storm water drains and to address waterlogging issues, an inter-departmental coordination committee has been formed by consensus of all departments.

"Secretary, PWD is the coordination committee chairman. Meetings of the committee will be held on regular basis to resolve inter-departmental issues, monitor desilting works, monitor and check waterlogging vulnerable locations," the flood order said.

Officials from other government agencies including the NDMC, MCD, Irrigation and Flood Control (I&FC), Delhi Cantonment Board, Delhi Development Authority, Delhi Jal Board, Delhi State Industrial ad Infrastructure Development Corporation, Delhi International Airport Limited, National Highways Authority of India, Indian Railways, Delhi Metro Rail Corporation, Delhi Urban Shelter Improvement Board among others, will be the members of the coordination committee.

"The coordination committee will monitor activities including desilting of storm water drains and sewers, cleaning of municipal solid waste from drains, addressing and resolving waterlogging vulnerable locations to check recurrence, status of operation of storm water pumps, inspection and cross inspection of desilting works and operation of pumps and resolve inter-departmental issues," the order stated.

Delhi witnessed waterlogging and massive traffic snarls on key stretches after the city received first monsoon showers on Thursday.

In a separate instruction, the divisional commissioner has asked district magistrates of 11 revenue districts in the capital to carry out "ground truthing" of desilting of drains carried out by the Flood and Irrigation department and other local bodies.

2 जुलाई • 2022 | राष्ट्रीय सहारा

प्रकृति आधारित शिक्षा के लिए काम करेगा डीडीए

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने 'प्रकृति आधारित शिक्षा एवं अनुभवात्मक गतिविधियों' पर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर' (डब्ल्यूडब्ल्यू एफ-इंडिया) के साथ मिलकर संजय वन में काम करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर प्राधिकरण ने एक करार किया है।

संजय वन राजधानी के दक्षिण-मध्य रिज क्षेत्र का हिस्सा है और वसंत कुंज से सटा यह इलाका 783 एकड़ में फैला है। प्राधिकरण का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू एफ-इंडिया पारिस्थितिक जैव विविधता को सुरक्षित करने और प्रकृति के बारे में शैक्षिक जागरूकता फैलाने के लिए काम करेगा। संरक्षण के मुद्दों को अपनी प्रतिबद्धता के साथ ज्ञान और गतिविधि भागीदार के रूप में काम करेगा। दिल्ली के लोगों विशेषकर बच्चों के बीच कम और प्रभावशाली उम्र में प्रकृति के साथ जोड़ने के लिए काम करेगा। जिससे उनकी प्रकृति के साथ एक समझ और बंधन पैदा हो सके। साथ ही शैक्षणिक अनुसंधान और वनस्पति जीवों का सरंक्षण भी करेगा। डीडीए ने इस प्राकृतिक क्षेत्र के रख-रखाव और देख-रेख के अलावा कई पहल की हैं।

डीडीए का डब्ल्यूडब्ल्यू एफ-इंडिया के साथ करार

इसमें वृक्षारोपण के जरिए वन चरित्र में बृद्धि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के साथ ही विरासत सरंचनाओं की बहाली और सरंक्षण, दिल्ली जल बोर्ड के साथ जलाशयों की सफाई आदि करेगा। गौरतलब है कि संजय वन 12वीं शताब्दी के ऐतिहासिक खंडहरों वाली प्राचीन अरावली श्रंखला का एक हिस्सा है। यह विभिन्न प्रकार की वनस्पति और जीवों से संपन्न घना जंगल है।

पंजाब केसरी

डीडीए का लर्निंग विद नेचर अभियान के तहत करार

डीडीए व डब्ल्यूडब्ल्यूएफ करेंगे धरोहरों का संरक्षण

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और वर्ल्ड वाइड फंड फार नेचर- इंडिया (डब्ल्यू डब्ल्यू एफ-इंडिया) मिलकर दक्षिणी दिल्ली स्थित संजय वन में प्राकृतिक वनस्पति और जीव-जंतुओं के संरक्षण से लेकर उनकी गतिविधियों पर निगरानी और वन के प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों को भी संरक्षित रखेंगे। लर्निंग विद् नेचर अभियान के तहत इसे अंजाम दिया जाएगा। इसी अभियान को लेकर दोनों संस्थाओं के बीच करार (एमओयू) हुआ। इस संबंध में डीडीए अधिकारी ने बताया कि संजय वन में प्रकृति आधारित शिक्षा और नेचर से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया (डब्ल्यू डब्ल्यू एफ-इंडिया) के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों संस्थान मिलकर लगभग 783 एकड़ में फैले संजय वन में पारिस्थितिक जैव विविधता संरक्षण और प्रकृति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ज्ञान और गतिविधि भागीदार के रूप में कार्य करेंगे। बच्चों में प्रकृति के साथ एक समझ और लगाव पैदा करने के उद्देश्य से यह अभियान सहायक साबित होगा।